गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 155
दि. 04.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

ऑपरेशन सिंदूर: आकाश में ध्वस्त हुए विमान और जवाबी ठोस दावे

(जीएनएस)। नई दिल्ली — भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए कथित 'ऑपरेशन सिंदूर' ने क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मायने बदल दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल ए.पी. सिंह की ओर से सार्वजनिक किए गए बयान में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के लगभग 12 विमान नष्ट किए गए। इन घातक कार्रवाइयों में कुछ विमान एयरबेस पर हैंगर और रनवे के पास ही तबाह किए गए जबकि कुछ को हवा में ही मार गिराया गया। कथित तौर पर हवा में मार करने वाली 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर छह विमान ध्वस्त किए गए — जिनमें पांच लड़ाकू विमान (एफ-16 या जेएफ-17 प्रकार) और एक AEW&C/सिग्नल इंटेलिजेंस विमान शामिल बताया गया है। साथ ही, पांच फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी एयरबेस पर नष्ट किए जाने की बात कही गई। एयरचीफ के बयान में एक स्पष्ट चुनौती भी थी: पाकिस्तान के वे दावे जिनमें उन्होंने भारतीय विमानों के कथित नुकसान और एयरबेसों पर हमले का उल्लेख किया था, वह "मनगढ़ंत कहानियाँ" बताकर खारिज कर

दिए गए। सिंह ने कहा कि अगर उनके पास ठोस तस्वीरें या सबूत हैं तो वे पेश करें; वरना ऐसे दावों पर बात करना बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई तस्वीर या प्रमाण नहीं दिखाई गया जो उनके दावों को पुष्ट करे। इस तर्क के साथ उन्होंने पाकिस्तान की ओर से दी जा रही सूचनाओं को उसकी प्रतिष्ठा बचाने के प्रयास के रूप में बताया और जनता को निर्णय के लिए खुला रहने का आग्रह किया। ऑपरेशन के विस्तृत प्रभावों का हवाला देते हुए एयरचीफ ने यह भी कहा कि भारतीय हवाई हमलों ने पाकिस्तान के कई संवेदनशील बुनियादी ढाँचों को निशाना बनाया। उनके अनुसार कम से कम चार स्थानों पर रडार प्रणाली, दो जगहों पर कमांड-कंट्रोल केंद्र, दो रनवे और तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हुए हैं; साथ ही चार-पाँच लड़ाकू विमान भी इस हमले में नुकसान झेल चुके हैं। इन लक्ष्यों पर सटीक ध्वनिक और हवाई चालों से मार कर ऑपरेशन को सीमित लक्ष्य के साथ संपन्न किया गया — ऐसा तरीका जो उनकी टिप्पणी के मुताबिक "युद्ध को बढ़ाए बिना लक्ष्य पर ही खत्म करने" की रणनीति का हिस्सा था। एयरचीफ ने यह भी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के सिंध और खैबर-पख्तूनख्वा क्षेत्रों में आतंकियों के नए ठिकाने बन रहे हैं और छोटे-छोटे संगठन आकार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं और आवश्यक होने पर उन ठिकानों को भी नष्ट करने की क्षमता है। इस प्रकार के संदेश से यह संकेत भी मिलता है कि ऑपरेशन केवल तत्काल झटका नहीं था बल्कि भविष्य की संभावनाओं और कार्रवाइयों के इशारे देने वाला भी कदम था। यह बयान तब आया है जब दोनों पक्ष सोशल मीडिया और आधिकारिक चैनलों पर अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सच्चाई तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है। एयरचीफ की चुनौतापूर्ण टिप्पणी — "अगर उनके पास सबूत हैं तो पेश करें" — ने घटनाक्रम को वैश्विक ध्यान की ओर मोड़ दिया है और साथ ही दोहराया कि ज़रूरी नहीं कि सार्वजनिक दावे वास्तविक नुकसान का प्रमाण हों। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन के परिणामों और प्रभावों का वास्तविक आकलन तभी विश्वसनीय होगा जब संयुक्त रूप से तथ्यों की पड़ताल हो सके। इस पूरे घटनाक्रम का जमीनी राजनीतिक और सुरक्षा अर्थ भी गहरा है।

भारत में तालिबान का कदम : पहली बार विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का दौरा, UNSC ने दी मंज़ूरी

(जीएनएस)। अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर अगस्त 2021 में कब्ज़ा करने के बाद से पहली बार तालिबान का कोई शीर्ष नेता भारत का आधिकारिक दौरा करने जा रहा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। यह यात्रा न केवल काबुल और नई दिल्ली के बीच संवाद का नया अध्याय है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय परिदृश्य में एक अहम मोड़ की तरह देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए मुत्ताक़ी को यात्रा प्रतिबंध से अस्थायी छूट प्रदान की है। परिषद की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 30 सितंबर 2025 को संकल्प 1988 (2011) के तहत बनी समिति ने मुत्ताक़ी को 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत की यात्रा की अनुमति दी है। यह छूट इसलिए भी अहम है क्योंकि तालिबान के कई शीर्ष नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है। भारत और तालिबान के बीच हाल के वर्षों में कई संकेत मिले हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं हैं। इसी साल मई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मुत्ताक़ी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसे कूटनीतिक जगत में बहुत अहम माना गया। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताक़ी की मुलाकात हुई थी, जिसे 2021 के

बाद दोनों पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता के रूप में देखा गया। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। यही कारण है कि मुत्ताक़ी किस प्रोटोकॉल के तहत भारत दौरे पर आएंगे, इस पर पूरी स्पष्टता नहीं है। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दौरा भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। एक तरफ तालिबान चाहता है कि भारत अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयरबेस के मुद्दे पर उसका समर्थन करे, वहीं भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को देखते हुए बेहद संतुलित रुख अपनाना होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तालिबान के साथ बातचीत तो करे, लेकिन इसे किसी औपचारिक मान्यता के रूप में न देखा जाए। भारत की चिंताएँ भी गहरी हैं, जिनमें आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका, अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय निवेश और सुरक्षा परिदृश्य प्रमुख हैं। दूसरी ओर तालिबान भारत को अपने विकास और निवेश परियोजनाओं में शामिल करना चाहता है, ताकि चीन और पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कुछ कम हो सके।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे दिन, राजनीतिक गतिरोध ने हजारों नौकरियों पर संकट खड़ा किया

(जीएनएस)। वॉशिंगटन से इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं, वे न केवल अमेरिकी राजनीति की जटिलता को उजागर करती हैं बल्कि लाखों लोगों के भविष्य पर मंडरा रहे अनिश्चित संकट की ओर भी इशारा करती हैं। अमेरिका की संघीय सरकार का शटडाउन अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और इसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर कांग्रेस और सड़कों तक महसूस की जा रही है। यह गतिरोध इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीति अपने चरम पर पहुँच जाती है तो प्रशासनिक तंत्र और आम जनता किस प्रकार उसके शिकार बनते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि यह बजट विवाद लंबा खिंचता है तो हजारों संघीय कर्मचारियों की नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। बजट कार्यालय (OMB) और विभिन्न एजेंसियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे उन विभागों की पहचान करें जिन पर इस संकट का सबसे गहरा असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में न केवल तनख्वाह रुक सकती है बल्कि बड़े पैमाने पर छंटनियाँ भी हो सकती हैं। यह घोषणा कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच गहरी चिंता का कारण बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यदि उन्होंने सरकार को खुला रखने के लिए सहयोग किया होता तो स्थिति इतनी विकट नहीं बनती। विवाद की असली जड़ स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी नीतियों में है, विशेषकर गैर-दस्तावेज़ी प्रवासियों को मेडिकेयर जैसी सुविधाएँ देने के मामले में। रिपब्लिकन मानते हैं कि इन योजनाओं पर खर्च करना अनावश्यक है और बजट घाटा बढ़ाता है, जबकि डेमोक्रेट्स इसे मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक ठहराते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शटडाउन को एक तरह से "अभूतपूर्व अवसर" बताते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि डेमोक्रेट्स ने उन्हें संघीय सरकार को नया रूप देने का मौका दिया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी लिखा कि शायद यही डेमोक्रेट्स का तरीका है "अमेरिका को जल्दी और चुपचाप फिर से महान बनाने का।" ट्रंप की यह टिप्पणी बताती है कि वे इस संकट को केवल आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार की तरह भी देख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता इस बात से और स्पष्ट होती है कि प्रशासन ने डेमोक्रेटिक राज्यों में चल रही अरबों डॉलर की परियोजनाओं की फंडिंग रोकने या स्थगित करने का फैसला किया है।

वांगचुक की गिरफ्तारी और पत्नी की न्याय की पुकार

(जीएनएस)। लद्दाख के जाने-माने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस समय विवादों और कानूनी लड़ाई के केंद्र में हैं। लेह हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में रखा गया है। इस गिरफ्तारी ने न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

अंगमो ने 2 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) दायर की। इस याचिका में उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके परिवार और करीबियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। यहां तक कि उनके एक कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन केवल वांगचुक को ही नहीं बल्कि उनके पूरे दायरे को दबाव में लेना

चाहता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो, 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी। इस हिंसा के लिए प्रशासन ने वांगचुक और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जेल भेज दिया गया। NSA का प्रयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। यही वजह है कि वांगचुक की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 2 अक्टूबर को लेह की स्थानीय जेल में बंद 56 आंदोलनकारियों में से 26 लोगों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन पर गंभीर धाराएं नहीं थीं। लेकिन 30 लोग अब भी जेल में हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है। इस अंतर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का परिणाम है।

वांगचुक केवल एक पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि लद्दाख की आवाज़ माने जाते हैं। उनकी पहचान एक शिक्षक, समाज सुधारक और स्थायी विकास के पैरोकार के रूप में रही है। उन्होंने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षों तक काम किया है और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए हैं। ऐसे व्यक्ति पर हिंसा भड़काने का आरोप और फिर NSA जैसी कठोर धारा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से विवाद खड़ा करता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि अदालत मानती है कि गिरफ्तारी अवैध है, तो यह न केवल वांगचुक की रिहाई का रास्ता खोलेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि नागरिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी इस लोकतंत्र की मूलभूत आत्मा हैं। दूसरी ओर, यदि सरकार और प्रशासन अपने आरोपों को प्रमाणित करने में सफल होते हैं, तो वांगचुक की रिहाई आसान नहीं होगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने लद्दाख के लोगों को झकझोर दिया है। वहां के स्थानीय समुदाय मानते हैं कि यह सिर्फ वांगचुक की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई अब तय करेगी कि पर्यावरणविद और समाज सुधारक सोनम वांगचुक जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें लंबे समय तक कैद में रहना पड़ेगा। फिलहाल, उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की यह याचिका न्याय की उम्मीद का एक मजबूत आधार बन गई है, जिस पर देश की नज़रें टिकी हुई हैं।

अब पूरी रात रोशन रहेगी मायानगरी, महाराष्ट्र सरकार ने दी 24 घंटे कारोबार की इजाज़त

(जीएनएस)। मुंबई। सपनों की नगरी मुंबई अब सचमुच कभी नहीं सोएगी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए दुकानों, होटलों, रेस्तरां, थिएटर और मनोरंजन स्थलों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। इस कदम से एक तरफ व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है तो दूसरी ओर हजारों नए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने साफ किया है कि यह सुविधा केवल उन प्रतिष्ठानों को मिलेगी जहां शराब की बिक्री या आपूर्ति नहीं होती। यानी वाइन शॉप, बीयर बार, डांस बार और हुक्का पार्लर जैसी जगहों पर पुराने समय-सीमा वाले नियम ही लागू रहेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब शहर में रेस्तरां, भोजनालय, मल्टीप्लेक्स, होटल और पब्लिक एंटरटेनमेंट सेंटर चौबीसों घंटे ग्राहकों के लिए खुले रह सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों को सप्ताह में 24 घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा ताकि श्रम कानूनों का पालन भी हो सके। इस फैसले को सरकार ने "महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन" के लिए अहम बताया है।

लेकिन शराब और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों को इस छूट से बाहर रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट

किया है कि वाइन शॉप, डांस बार, डिस्कोथेक और परमिट रूम्स पहले जैसे समय-सीमा वाले नियमों से ही संचालित होंगे। इससे पहले 2017 और 2020 में भी ऐसे प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके थे। यह फैसला नया जरूर है, लेकिन इसका इतिहास पुराना है। मुंबई में नाइटलाइफ को वैध रूप से बढ़ावा देने की मांग पहली बार 2013 में उठी थी, जब मुंबई महानगरपालिका ने इस प्रस्ताव को पारित किया। इसके बाद 2015 में मुंबई पुलिस ने भी मंजूरी दे दी थी। 2021 में अधिसूचना जारी की गई, लेकिन तत्कालीन फडणवीस सरकार ने इसे लागू नहीं किया। 2020 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार ने इसे हरी झंडी दी थी, जिस पर भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने कड़ा विरोध जताया था। भाजपा नेताओं का कहना था कि यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और समाज की संस्कृति के खिलाफ है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने तब ट्वीट कर तंज कसा था—"चलो अब मुंबई में भी रात का खेल खेलते हैं।" अब जबकि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इसी नीति को लागू कर दिया है, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने पहले इसी "मुंबई 24/7" योजना का विरोध किया था और अब सत्ता में आकर वही लागू कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पहले जिन मुद्दों पर संस्कृति और सुरक्षा की दुहाई दी जाती थी, अब वही सब ठीक कैसे हो गया। फिलहाल यह फैसला मुंबई और अन्य बड़े शहरों के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। होटल और रेस्तरां मालिक इसे अपने कारोबार के लिए जीवनदान बता रहे हैं, जबकि आम लोग इस बदलाव को शहर की आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इतना तय है कि अब मायानगरी सचमुच 24 घंटे जगमगाती नजर आएगी।

रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर मुठभेड़ के बाद धराए, कई राज्यों में फिरौती और फायरिंग की वारदातों से जुड़े धागे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अपराध जगत पर बड़ा प्रहार करते हुए पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार तड़के कापसहेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही गैंग है जो हाल के वर्षों में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक अपने आतंक और रंगदारी के धंधे से कुख्यात हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए शूटरों की पहचान आकाश राजपूत और महिपाल मीना के रूप में हुई है। दोनों विदेश में बैठे सरगनाओं के इशारे पर कारोबारियों और संस्थानों को धमकाकर मोटी रकम वसूलने के धंधे में सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह स्पेशल सेल की टीम को खबर मिली कि दोनों आरोपी बाइक पर कापसहेड़ा इलाके से गुजरेंगे। घेराबंदी कर जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आकाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अब इनसे गिरोह की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ हो रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आकाश जुलाई महीने में गुजरात के कच्छ जिले से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और रंगदारी मामले में शामिल था। उसने विदेश में छिपे गैंगस्टर कीर्ति सिंह झाला के इशारे पर एक कारोबारी का अपहरण कर 100 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। इस वारदात के बाद से ही वह पुलिस के रडार पर

था और श्रीगंगानगर पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने हरियाणा के करनाल स्थित मीनाक्षी अस्पताल के बाहर भी फायरिंग की थी। अस्पताल मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और जब उसने देने से इनकार कर दिया, तो डर फैलाने के लिए गोलीबारी की गई। इस मामले में महिपाल पहले जेल भी जा चुका है और हाल ही में जमानत पर छूटा था। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा अब छोटे-छोटे अपराधी गिरोहों और शूटरों को जोड़कर अपने नेटवर्क को बड़ा और खतरनाक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आकाश और महिपाल को इसी सिलसिले में गैंग में शामिल किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन गिरफ्तारियों से न केवल दिल्ली बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी चल रहे अपराधों की कई परतें खुलने की संभावना है। इस कार्रवाई के बाद एक ओर जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर यह भी साफ हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिपे गैंगस्टरों और स्थानीय अपराधियों के बीच गठजोड़ अब भी बरकरार है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क पर और बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।

करूर भगदड़ की गूंज और न्याय की उम्मीद

(जीएनएस)। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भयावह भगदड़ ने सैकड़ों परिवारों को गहरे शोक और असहनीय पीड़ा में धकेल दिया। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के रोड शो के दौरान बेकाबू हुई भीड़ अचानक इस कदर अफरातफरी में बदल गई कि 41 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे और 100 से ज्यादा घायल हो गए। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राजनीतिक रैलियों और शक्ति प्रदर्शन में जनता की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने साफ शब्दों में कहा कि यह घटना पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन आयोजनकर्ता पार्टी TVK ने न तो कोई खेद जताया और न ही पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अदालत ने कहा कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना चुप्पी से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं। अदालत ने पार्टी के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपनी आंखें बंद कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सीबीआई जांच की मांग को अदालत ने ठुकरा दिया और इसके स्थान पर एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया। इस SIT की कमान तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल असरा गर्ग को सौंपी गई है। अदालत ने माना कि स्थानीय स्तर पर जांच तेजी से होगी और सच्चाई सामने आएगी। साथ ही, स्टालिन सरकार को नोटिस जारी कर अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर जवाब देने को कहा गया है, ताकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई वास्तविक पीड़ित या पीड़ित परिवार मदद के लिए आगे आता है तो न्यायपालिका उसके साथ खड़ी होगी। यह घटना केवल न्यायिक दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी गहरी बहस छेड़ दी। अदालत ने TVK के जिला सचिव एन. सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को भी सख्ती से खारिज कर दिया और सवाल उठाया कि जब वे आयोजनकर्ता थे तो भीड़ पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा गया। अदालत ने यह भी पूछा कि जब कार्यकर्ता बेकाबू हो रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे और अफरातफरी फैला रहे थे, तो जिम्मेदार लोग चुप क्यों रहे। यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि अदालत केवल घटना को नहीं बल्कि उसकी जड़ में मौजूद लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता को भी पहचान रही है।

करूर की यह त्रासदी अब केवल एक हादसा नहीं रही, बल्कि यह तमिलनाडु और पूरे देश के लिए चेतावनी बन गई है। राजनीतिक लोकप्रियता के नाम पर जुटाई गई भीड़ अगर मौत का कारण बन जाए, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाती है। SIT की जांच अब इस बात पर केंद्रित होगी कि घटना के पीछे किस स्तर की लापरवाही रही और जिम्मेदार लोगों को कैसे कठघरे में खड़ा किया जाए। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनसभाओं और राजनीतिक आयोजनों में केवल भीड़ जुटाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। करूर की सड़कों पर हुई यह त्रासदी लंबे समय तक याद दिलाती रहेगी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भीड़ प्रबंधन की चूक किस तरह मासूमों की जान ले लेती है।

संपादकीय

ऑनलाइन सेवाओं हेतु जागरूक करना जरूरी

कैसी विडंबना है कि भोले-भाले लोगों से छल करके खून-पसीने से हासिल जीवनभर की पूंजी ऑनलाइन डकैती में लूट ली जाती है। जिसकी वापसी के लिए तंत्र की कोई जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं है। जब तंत्र लगातार ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिये प्रेरित करता है तो उसे जनधन की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़े इस संकटपूर्ण स्थिति का खुलासा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि वर्ष 2023 में साइबर क्राइम की घटनाओं में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई है। जिसके आने वाले वर्षों में और अधिक होने की आशंका जतायी जा रही है। जो इस बात का प्रमाण है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से निबटना अब दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। निश्चित रूप से साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के आंकड़े जुटाने की एनसीआरबी की पहल महत्वपूर्ण है, जो इस संकट से निबटने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अपराधों से निबटने के लिये कैसे रणनीति बनाते हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि कैसे वे साइबर अपराधियों के संजाल में फंसने से बच सकते हैं। यूं तो डेटा सुरक्षा के लिये तमाम दिशा-निर्देश सरकार के विभिन्न संगठनों की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन आज भी पुरानी पीढ़ी के तमाम लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सुविधाओं के उपयोग को लेकर पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं होते। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि दैनिक जीवन में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हुए अपने गोपनीय डेटा की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन विडंबना यह है कि साइबर अपराधी नित नए तौर-तरीकों से लोगों को लूटने लगते हैं। कुछ समय पहले साइबर लुटेरों ने स्पूफिंग तकनीक से लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। वे सोशल मीडिया अकाउंट में घुसपैठ करके धन की उगाही करने लगते। व्यक्ति को संकट में दिखाकर उसके रिश्तेदारों से धन ऐंठने लगते।

विडंबना यह है कि साइबर ठगी की तकनीक उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों और ई-मेल खातों तक भी पहुंच गई। दरअसल, कभी हैकिंग, तो कभी स्पूफिंग के कपटपूर्ण छल का मकसद लोगों की जमा-पूंजी को निशाना बनाना ही रहा है। दरअसल, जब तक लोग ठगी के इन तौर-तरीकों को समझ पाते, साइबर ठग नई तकनीक के सहारे लोगों को भ्रमित कर चूना लगाने की नई कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच सवाल उठता है कि हमारा तंत्र इन घटनाओं में पर प्रभावी रोक लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता। आखिर फोन व कंप्यूटर में मजबूत एंटी वायरस और इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर क्यों कामयाब नहीं होते। आखिर क्यों साइबर घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। इन पर रोक के लिये कोई कारगर व्यवस्था व मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है। दूरसंचार नियामक ट्राई की अपनी सीमाएं हैं। संकट यह भी है कि ज्यादातर साइबर अपराध की घटनाएं प्रॉक्सी यानी छद्म सर्वर या फिर वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिये अंजाम दी जाती हैं। ज्यादातर अपराध भारत के बाहर से संचालित होते हैं। यही वजह है कि जालसाज विदेश में बैठकर भी भारत के अपराधियों की मदद से धोखाधड़ी का नेटवर्क बना लते हैं। इससे वे भारतीय नागरिकों को चपत लगाने में सफल हो जाते हैं। निस्संदेह, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सावधानी और सजगता-सतर्कता मददगार साबित हो सकती है। खासकर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते वक्त अतिरिक्त सावधानी से ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी बैंक का कोई अधिकारी खाताधारक से निजी व गोपनीय जानकारी नहीं पूछता है। वो कभी फोन व ई-मेल से ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। इसलिए जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक खाते की सुरक्षा से जुड़े पासवर्ड,पिन, सीवीवी तथा खाता नंबर की जानकारी मेल या फोन से मांगता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसी ही सावधानी हाऊस अरेस्ट के मामलों में भी बरतनी चाहिए। साथ ही असली-नकली वेबसाइट की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

सत्ता संघर्ष में एर्दोआन के उत्तराधिकारी का प्रश्न

> तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की सत्ता संकट में है। आर्थिक मंदी, डिग्री विवाद और व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर बहस तेज़ हो रही है, जिससे पार्टी में अस्थिरता बढ़ गई है। इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता एक्रेम इमामोग्लू को गिरफ्तार किया जाना इस स्थिति को और जटिल बना रहा है।

एर्दोआन ख़ैरियत से नहीं हैं। एर्दोआन के करीबी लोगों में, उनके बाद के भविष्य को लेकर बहस फिर से तेज़ हो गई है। हालांकि पार्टी का एक हिस्सा दावा करता है कि राष्ट्रपति रेजेप तैय्यिप एर्दोआन खुद 2028 में पद छोड़ने का इरादा नहीं रखते, लेकिन पार्टी की अंदरूनी स्थिति उबाल पर है। वर्ष 2017 में एक जनमत संग्रह के बाद, तुर्की की सरकार संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली में बदल गई।

तुर्की में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम तेज़ी से चर्चा में आ रहे हैं। हकान फ़िदान 2010 से 2023 तक तुर्की ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख रहे हैं और अब विदेश मंत्री हैं। वह एर्दोआन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं, लेकिन राष्ट्रपति परिवार में उन्हें लेकर थोड़ी सावधानी बरती जाती है। इब्राहिम कालिन 2014 से तुर्की राष्ट्रपति के प्रेस सचिव और 2023 से राष्ट्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख हैं। उन्हें एक बुद्धिजीवी और शासन के सबसे करीबी विचारकों में से एक माना जाता है। बिलाल एर्दोआन राष्ट्रपति के बेटे हैं, मुख्य 'वंशवादी' उत्तराधिकारी और अखिल तुर्कवाद के दूत के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी छवि कमज़ोर है। उनका अतीत निंदनीय रहा है, ख़ासकर 2013 के 'टेलीफ़ोन रिकॉर्ड' के दौरान 'लाखों लोगों के लापता होने के मामले' को लेकर।

सेल्कुक बयारकतार एर्दोआन के दामाद हैं, जो बयारकतार ड्रोन के डिज़ाइनर हैं। वे तुर्की राष्ट्रवादियों के प्रतीक हैं। बेरात अल्बयारक एक और दामाद हैं, जो पूर्व वित्त और ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में तुर्की में संकट शुरू हुआ था। लेकिन आर्थिक विफलता और घोटालों के बाद, उन्हें अपना पद खोना पड़ा। सुलेमान सोयलू एक पूर्व गृह मंत्री हैं जो सुरक्षा हलकों में प्रभावशाली हैं। लेकिन पेकर के घोटालों और आरोपों ने उनकी दावेदारी बहुत कमज़ोर कर दी। विदेश

मंत्री हकान फ़िदान रूस के लिए सबसे अच्छा विकल्प लगता है। कठोर, लेकिन व्यावहारिक। सबसे विवादास्पद सेल्कुक बयारकतार हैं, जो रूसी संघ के ख़िलाफ़ पश्चिमी गठबंधन के पैरोकार हैं।

वह साल 1994 था, जब एर्दोआन इस्तांबुल के मेयर बने, जबकि उनके अब कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक्रेम इमामोग्लू ने व्यवसाय प्रशासन संकाय से स्नातक किया। इमामोग्लू और एर्दोआन ने अपने राजनीतिक करियर को एक जैसे तरीक़े से बनाया है। दोनों इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, और दोनों ही उस पद पर रहते जेल गए हैं। एर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने, लेकिन पांच साल बाद एक राजनीतिक रैली में राष्ट्रवादी कविता — 'मीनारें हमारी संगीनें हैं और गुंबद हमारे हेलमेट हैं।' पढ़ने के बाद धार्मिक नफ़रत भड़काने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। उस समय धर्मनिरपेक्ष अदालतों ने कविता को एक ख़तरे के रूप में देखा था। राष्ट्रपति बनने से पहले एर्दोआन प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 20 से ज़्यादा वर्षों तक तुर्की पर कब्ज़ा बनाए रखा और वहां के लोकतंत्र पर अपनी पकड़ मज़बूत की। और एर्दोआन के ही रास्ते पर चलते हुए इमामोग्लू तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर बने। इमामोग्लू लंबे समय से अपनी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के नेता रहे हैं और अब उन्हें एर्दोआन का सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।

19 मार्च, 2025 को, इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक्रेम इमामोग्लू को फ़र्ज़ी डिग्री, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, धन शोधन और आतंकवाद, विशेष रूप से पीकेके का समर्थन करने के संदेह में तुर्की पुलिस ने हिरासत में लिया था।

तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार द्वारा उच्च शिक्षा पूरी कर ली होनी चाहिए। लेकिन 18 मार्च को, देश की विपक्षी पार्टी द्वारा इमामोग्लू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने और एर्दोआन के ख़िलाफ़ आधिकारिक चुनाव लड़ने से कुछ ही दिन पहले, उनकी डिग्री रद्द कर दी गई।

इस गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दो हज़ार से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से अधिकांश अभी जेल में हैं। लोगों ने राष्ट्रपति एर्दोआन की डिग्री को भी जुगाड़ वाला बताया। राष्ट्रपति एर्दोआन की आधिकारिक जीवनी, 'एक्सटर्नल', में लिखा है कि उन्होंने 1981 में मरमरा विश्वविद्यालय के आर्थिक और वाणिज्यिक विज्ञान संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।

लेकिन हाल के दिनों में तुर्कों ने ट्विटर पर (या तो अपनी डिग्री दिखाओ या फिर इस्तीफ़ा) वायरल करते हुए राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इस हैशटैग का इस्तेमाल करके हजारों री-ट्वीट किए गए हैं। एक म्यूज़िक वीडियो भी है, जिसमें राष्ट्रपति से अपनी उच्च शिक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रपति एर्दोआन को इस मामले में मरमरा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से कोई मदद नहीं मिली है, जहां बताया गया है कि उपरोक्त संकाय कभी अस्तित्व में ही नहीं था, बल्कि आर्थिक एवं प्रशासनिक विज्ञान संकाय की स्थापना 1982 में हुई थी।

एर्दोआन की डिग्री की प्रामाणिकता पर संदेह सबसे पहले 2014 में, उनके राष्ट्रपति चुने जाने से पहले, एक विपक्षी सांसद ने जताया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2014 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मरमरा विश्वविद्यालय के अभिलेखागार बंद कर दिए गए थे। और पिछले कुछ दिनों में पुरानी रिपोर्टों के फिर से साझा होने के परिणामस्वरूप यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जिसमें कहा गया है कि मरमरा विश्वविद्यालय के अभिलेखागार फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति की डिग्री नहीं मिल रही है। तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए आधिकारिक तौर पर चार साल की डिग्री होना अनिवार्य शर्त है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अगर उनकी डिग्री असली नहीं पाई गई, तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

एर्दोआन चाहे जितना भी राष्ट्रवाद बघार लें, इस देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हालत में है। एर्दोआन के अपने मतदाता भी उच्च मुद्रास्फीति, आय असमानता, आवास और रसोई की लागत, और युवाओं के लिए बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। बेहतर जीवन बनाने के आर्थिक अवसर और भी अधिक मायावी होते जा रहे हैं। वास्तव में, जैसे ही डिप्लोमा रद्द के विरुद्ध लोग सड़क पर उतरे, बाज़ारों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय बैंक को मुद्रा भंडार से पैसे निकालने पड़े। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अब तक 40 अरब डॉलर का उपयोग करना पड़ा।

तुर्की में सबसे बदनाम अदालतें हुई हैं, जो एर्दोआन की तरफ़दारी कर रही हैं। दो साल से तुर्की का जेन-जेड उनकी असलियत उजागर करने में लगा है। एर्दोआन कब तक जेन-जेड को दबाए रखेंगे? यह भी एक सवाल है।

प्रेरणा

सुलझाने का धैर्य : कबीर का जीवन-संदेश

कबीरदास साधु, कवि और संत ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे ज्ञानी थे। वे जिस भी काम को करते थे, उसमें साधना और अनुभव का बोध झलकता था। उनके जीवन का हर क्षण उनके शिष्यों और समाज के लिए शिक्षा का अवसर बन जाता था।

एक दिन वे अपने चरखे पर बैठकर सूत कात रहे थे। धागा बड़ी आसानी से निकल रहा था, लेकिन अचानक एक जगह जाकर उलझ गया। चरखे की गति रुक गई और धागे में गांठें पड़ गईं। पास बैठा शिष्य बड़ी देर से यह दृश्य देख रहा था। वह बेचैन होकर बोला – "गुरुजी, यह धागा बहुत उलझ गया है। इसे सुलझाने में समय बरबाद करना ठीक नहीं है। इसे काट दीजिए और नया धागा शुरू कीजिए।"

कबीर ने अपने सहज मुस्कान के साथ शिष्य की ओर देखा। उनकी आँखों में गहराई थी और चेहरे पर धैर्य की झलक। वे बोले – "नहीं बेटा, धागा काटना तो सबसे आसान काम है, लेकिन उलझे हुए धागे को सुलझाना ही असली साधना है। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयों और उलझनों से भाग

जाना सरल है, पर धैर्य रखकर उन्हें सुलझाना ही सच्चा ज्ञान है।"

शिष्य अभी भी आश्वस्त नहीं हुआ। उसने फिर कहा – "गुरुजी, पर इसमें बहुत समय लग जाएगा। हम नया धागा शुरू कर देंगे तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा।"

कबीर ने गहरी साँस लेते हुए उत्तर दिया – "समय लगना कोई दोष नहीं है, लेकिन अधूरा छोड़ देना दोष है। अगर हम धागे को काट देंगे तो नया धागा तो शुरू हो जाएगा, पर यह गांठ अधूरी रह जाएगी। जैसे धागा अधूरा रहेगा, वैसे ही जीवन में भी जब हम उलझनों को काटकर छोड़ देते हैं, तब रिश्ते, समाज और आत्मा अधूरेपन का बोझ ढोते रहते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से उलझनों को सुलझाना सीख जाता है, वही सच्चा साधक है।"

शिष्य ने पहली बार महसूस किया कि गुरु केवल चरखा नहीं चला रहे, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य समझा रहे हैं। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह कभी कठिनाइयों से भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य से सुलझाएगा।

कबीर की यह सीख केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। जीवन की कठिनाइयाँ धागे की तरह उलझती हैं। कभी रिश्ते जटिल हो जाते हैं, कभी परिस्थितियाँ संकट में डाल देती हैं, कभी मन अशांत होकर गांठों से भर जाता है। ऐसे समय में धागा काट देना यानी रिश्ता तोड़ देना, जिम्मेदारी छोड़ देना या भाग जाना आसान लगता है। लेकिन यही पल साधना का होता है। धैर्य, विवेक और निरंतर प्रयास से जब हम उन उलझनों को सुलझाते हैं, तभी जीवन का ताना-बाना मजबूत और सुंदर बनता है।

तबाही का सबब बन सकती हैं ग्लेशियर झीलें

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियर झीलों की संख्या और आकार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि निचले इलाकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, क्योंकि इन झीलों के टूटने से बाढ़ जैसी आपदाएं आ सकती हैं। उच्च हिमालय में झीलों का यह विस्तार वैज्ञानिकों और प्रशासन दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर झीलों का तेजी से विस्तार भविष्य में 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी आपदाओं का कारण बन सकता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 13 बेहद खतरनाक और 5 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। कई झीलें मौसम व भौगोलिक कारणों से बनती-बिगड़ती रहती हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में नई ग्लेशियर झील के आकार में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।

केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अरुणाचल में 197 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। ये अपना खतरनाक स्तर पर विस्तार कर रही हैं। इनके बाद लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड में झीलें हैं। एनडीएमए ने उत्तराखंड की इन खतरनाक 13 झीलों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पिछले दिनों में गंगोत्री की केदारताल और चमोली में वसुतारा झील का काफी विस्तार हुआ है। इन झीलों के गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. एम.पी.एस. बिष्ट द्वारा वर्ष 2014 और 2023 के उपग्रह चित्रों के अध्ययन से यह चिंताजनक खुलासा हुआ है। उनके मुताबिक ये झीलें हिमनद के असंगठित मलबे—मोराइन डैम की रुकावट से बनी हैं। उनका मानना है कि इस खतरे को देखते हुए सरकारों और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को समय रहते इन झीलों का आकलन कर तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। वास्तव में उत्तरकाशी की धराली की घटना ने उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों के बढ़ते खतरे को फिर से चर्चा में ला दिया है।

वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान चौराबाड़ी ग्लेशियर झील के फटने से हुई तबाही ने ग्लेशियर झीलों के खतरे को गंभीर मुद्दा बना दिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 968 ग्लेशियर और कई हजार ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। इन झीलों में अत्यधिक बर्फ पिघलने से अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता है। इन झीलों का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका लगातार बनी रहती है।

हकीकत यह है कि मौसम के इस बदलते पैटर्न के बारे में बहुत कुछ समझना अभी भी बाकी है। इसलिए पिछले तकरीबन तीस सालों के आंकड़ों का गहनता से आकलन बेहद जरूरी है। आपदाओं के पूर्वानुमान को भी बेहतर बनाना समय की मांग है। यही नहीं, आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिमालय के जटिल और प्राचीन भूभाग पर कार्बन युक्त एरोसोल के अध्ययन को नजरंदाज करना बहुत बड़ी चूक होगी।

अध्ययन में खुलासा हुआ है कि हिमालय में वायु प्रदूषण में जीवाश्म ईंधन के जलने का ज्यादा असर पड़ रहा है। हिमालय अंचल में गाड़ियों की बढ़ती तादाद हवा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का अहम कारण है। हिमालयी बस्तियों और शहरों के बढ़ते बोझ से अब हांफने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर पिघलकर बनी झीलें जल प्रलय को आमंत्रण दे रही हैं। इसरो की मानें तो हिमालय क्षेत्र की 2432 ग्लेशियर झीलों में से 672 झीलों का तो आकार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इनमें से भारत में मौजूद 130 झीलों के टूटने का खतरा हमेशा बना हुआ है।

इसमें दो राय नहीं कि दिनोंदिन बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की आंधी ग्लेशियरों के विनाश का सबब बन रही है। समुद्र के जलस्तर में वर्ष 1900 की तुलना में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी और उसमें हो रही दिन-ब-दिन तेजी से वृद्धि, जिसके चलते कुछ द्वीप और तटीय इलाके डूबते जा रहे हैं। कुछ महानगरों-शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है, बाढ़ की विनाशलीला बस्तियों को लील रही है, वहीं सूखा गांवों को वीरान बनाने की राह पर है। ऐसी विषम स्थिति में ग्लेशियरों को बचाना महज बर्फ को बचाना नहीं है बल्कि अपने भविष्य को बचाना है।

वैज्ञानिकों के शोध-अध्ययन इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में ग्लेशियर झीलों में बहुतेरी ऐसी हैं जिनका आकार जून, 2025 के दौरान बढ़ा है। याद रखना होगा कि ग्लेशियर मात्र बर्फीले शिखर ही नहीं हैं, वे हमारे भविष्य की जड़ें हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि बर्फ के पिघलने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र बदल जाता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इन बढ़ते खतरों से निपटने की दिशा में हमें तत्काल कार्रवाई, फंडिंग के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में मानवीय दखलंदाजी पर अंकुश, जलवायु परिवर्तन के दानव और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगानी ही होगी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हिमालय की जल धाराएं मौन हो जाएंगी, हम बूंद-बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे, खेत सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। आपदा प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन जागरूकता, सतर्कता और सावधानी से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं।

अभियान

रहस्यमयी शिवधाम और घंटियों का अद्भुत रहस्य

भारत की भूमि पर धर्म, अध्यात्म और रहस्य का ऐसा अनोखा संगम है, जो हर युग में भक्तों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। भगवान शिव के मंदिरों की बात हो तो हर एक मंदिर की अपनी अनूठी परंपरा, मान्यता और रहस्य होते हैं। कहीं शिव को मदिरा चढ़ाई जाती है, कहीं भांग और धतूरा, तो कहीं पूजा के समय विशेष वाद्य बजाए जाते हैं। लेकिन कुछ शिव मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ घंटी बजाता है। इन स्थानों पर घंटी केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का वह माध्यम है जो भक्त और भगवान के बीच सेतु बनाती है। हिंदू धर्म में घंटी को पवित्रता और चेतना का प्रतीक माना गया है। यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई साधक मंदिर की घंटी बजाता है तो उस ध्वनि से वातावरण की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और स्थान पवित्र हो उठता है। साथ ही घंटी की गूंज साधक के भीतर की चंचलता को शांत करके मन को एकाग्र करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि घंटी

की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि "ॐ" की प्रतिध्वनि होती है, जो साधक को दिव्यता से जोड़ती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर इसका सबसे प्राचीन और अद्भुत उदाहरण है। आठवीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। यहाँ की परंपरा यह है कि भक्त जब भी शिव के दरबार में प्रवेश करता है तो सबसे पहले घंटी बजाकर अपनी चेतना को जागृत करता है। यहाँ घंटी बजाना केवल शिव को जगाने का कार्य नहीं बल्कि स्वयं के भीतर सुप्त पड़े आध्यात्मिक ऊर्जा-तत्व को सक्रिय करने की प्रक्रिया मानी जाती है। मंदिर की विशाल दीवारों और गर्भगृह में गूंजती घंटियों की ध्वनि साधकों को ध्यान की अवस्था में ले जाती है। विश्वास है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से घंटी बजाकर पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी घंटी की परंपरा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। बारह ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान रखने वाला यह मंदिर एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यहाँ की परंपरा यह है कि कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार पर लगी घंटी को अवश्य बजाए। इसे केवल पूजा का प्रारंभ मानना भूल होगी। यह वास्तव में शिव को अपनी उपस्थिति का संकेत है, मानो भक्त कह रहा हो—"हे महादेव! मैं आपके द्वार पर आया हूँ, अपनी नकारात्मकता बाहर छोड़कर आपकी शरण में प्रवेश कर रहा हूँ।" यहाँ घंटी की गूंज भक्त के मन को पवित्र करती है और उसकी प्रार्थना सीधे शिव तक पहुँचती है। हरियाणा का घंटेश्वर महादेव मंदिर तो घंटियों की ध्वनि का अद्भुत संसार है। यहाँ प्रवेश करते ही भक्त को सैकड़ों छोटी-बड़ी घंटियों की झंकार सुनाई देती है, जो मंदिर की पहचान है। भक्त मानते हैं कि यहाँ अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेकर घंटी बजाता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस मंदिर में एक विशेष परंपरा है कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह यहाँ बड़ी पीतल की घंटी चढ़ाता है। उन घंटियों को सम्मानपूर्वक मंदिर परिसर में टांग दिया जाता है। सावन के पावन महीने और महाशिवरात्रि पर जब हजारों-लाखों भक्त यहाँ एक साथ घंटी बजाते हैं तो वातावरण इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली हो उठता है कि साधक स्वयं को दिव्यता में खोया हुआ महसूस करता है। इन तीनों शिवधामों में घंटी का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है। यह वह आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझा और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। घंटी की ध्वनि जब वायु में गूंजती है तो वह स्पंदन उत्पन्न करती है, जो साधक के शरीर के ऊर्जा-केंद्रों यानी चक्रों को संतुलित करती है। योग और तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है कि घंटी की ध्वनि साधना की स्थिति को स्थिर करती है और साधक के भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती है। इस प्रकार महादेव के ये रहस्यमयी धाम केवल ईंट-पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि अध्यात्म, ऊर्जा और चेतना के जीवंत केंद्र हैं। यहाँ घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक अदृश्य रहस्य का उद्घाटन है। शायद यही कारण है कि जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है और श्रद्धा से घंटी बजाता है, उसका मन दिव्यता से भर उठता है और उसकी आत्मा महादेव की शरण में शांति का अनुभव करती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक, 129 एजेंडों पर लगी मुहर, चुनाव से पहले जनता और कर्मचारियों को बड़े तोहफ़े

(जीएनएस)। पटना में दशहरा के अगले दिन हुई नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक को विधानसभा चुनाव से पहले की अंतिम बड़ी बैठक माना जा रहा है। इस बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें राज्य के कर्मचारियों से लेकर छात्रों, बेरोजगार युवाओं, अधिवक्ताओं और धार्मिक स्थलों तक से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। यह निर्णय न केवल चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं बल्कि बिहार के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर भी व्यापक असर डालने वाले साबित हो सकते हैं।

सबसे पहले कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। अब राज्यकर्मियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह कदम केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप उठाया गया। साथ ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़े एएनएम कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया। शहरी क्षेत्रों में संविदा पर नियोजित एएनएम का वेतन 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हर साल पाँच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान

किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला किया। स्कूली छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। पहली से चौथी कक्षा तक के छात्रों को अब 600 की जगह 1200 रुपये मिलेंगे। इसी तरह पाँचवीं-छठी के लिए 1200 से बढ़ाकर 2400 रुपये, सातवीं-आठवीं के लिए 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपये और नौवीं-दसवीं के लिए 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए तीन अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने बड़े पैमाने पर नए पद सृजित करने का निर्णय भी लिया है। वानिकी महाविद्यालय, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र और संजय गांधी जैविक उद्यान के साथ-साथ नौ नए वन प्रमंडलों के गठन के लिए कुल हज़ारों पदों का सृजन किया गया है। यह निर्णय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन को सुदृढ़ करेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास पर भी जोर दिया गया है। बेगूसराय जिले के सिमरिया धाम के लिए लगभग 65 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है। वहीं, वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का विकास भी विशेष परामर्शदात्री संस्था को सौंपा गया है। इसके अलावा पूर्णिया और मोतिहारी की जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाते हुए स्नातक स्तर के बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक हर महीने 1000 रुपये का भत्ता देने की स्वीकृति दी है। अधिवक्ताओं को भी सरकार ने राहत दी है। नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक 5000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। अधिवक्ता संघ के लिए ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु 5 लाख रुपये की सहायता और अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि देने का भी फैसला हुआ है। शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ को भी इस बैठक में राहत मिली। इन्हें प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में अब 3405 की जगह 12,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही स्मार्टफोन खरीदने के लिए हर शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ को 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी। सेना के सेवानिवृत्त चालकों का मानदेय भी 25,750 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी और लचीला बनाया गया है। अब चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध होगा। छोटे ऋणों की वापसी अवधि पाँच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष और बड़े ऋणों की वापसी अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई है। इस अंतिम कैबिनेट बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश की है—कर्मचारी, छात्र, बेरोजगार, अधिवक्ता, धार्मिक संस्थान, पर्यावरण क्षेत्र और ग्रामीण विकास सबको ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बैठक सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि जनता को चुनावी तोहफ़ा देने की बड़ी कवायद है।

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, पटना को मिला नया कमिश्नर और चंद्रशेखर पहुंचे नीतीश टीम में

(जीएनएस)। पटना में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नीतीश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कई आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव पटना प्रमंडल के कमिश्नर पद पर हुआ है।

पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर को बनाया गया है। वे पहले पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं और अब उन्हें प्रमंडल कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे बिहार राज्य निर्माण विकास निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे।

वहीं, मौजूदा कमिश्नर डॉ. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। चंद्रशेखर पहले पटना के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम का अहम हिस्सा बन गए हैं। इस फेरबदल में यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नया नगर

आयुक्त बनाया गया है। वे इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव की भूमिका निभा रहे थे। हिमांशु शर्मा को स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि शीर्षत कपिल अशोक को कम्फेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनुमंडल स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। कृतिका मिश्रा को गोगरी (खगड़िया) अनुमंडल का एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा, प्रधुम्न सिंह यादव को पटना नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के भीतर होने वाली बताई जा रही है। इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों में लगातार आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। विपक्ष इसे चुनावी तैयारी बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि नीतीश सरकार इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है।

बिहार की राजनीति और चुनावी गणित को देखते हुए यह फेरबदल न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार चुनाव से पहले प्रशासनिक मोर्चे को पूरी तरह नियंत्रण में रखना चाहती है।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियाँ तेज, सरकार जल्द ले सकती है फैसला

(जीएनएस)। झारखंड की राजनीति में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। लंबे समय से टल रहे इन चुनावों को लेकर अब राज्य में नई ऊर्जा दिख रही है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अलका तिवारी ने कार्यभार संभाला और सबसे पहले आयोग की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की गंभीरता दिखाई और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पहुँचीं। इस दौरान आयोग के कामकाज, अब तक की प्रक्रिया और आगे की दिशा पर चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम ने स्पष्ट किया है कि आयोग नगर निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है और अब केवल सरकार के निर्णय का इंतजार है। नगर विकास विभाग को वार्डों और पदों का निर्धारण कर आरक्षण व्यवस्था तय करनी है, जिसके आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। आरक्षण का यह पहलू अहम है, क्योंकि इसके तय होते ही चुनाव की तारीखें भी सामने आ सकेंगी। इसी बीच नगर निकाय चुनाव का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव टालने पर कड़ा रुख दिखाया था और साफ संकेत दिए थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नगर निकाय चुनाव को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना उचित नहीं है। अदालत की इस सख्ती के बाद यह संभावना और भी बढ़ गई है कि सरकार 14 अक्टूबर से पहले चुनाव को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी का कहना है कि नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब चुनाव में कोई बड़ी बाधा नहीं है। झारखंड के शहरी निकायों में लंबे समय से चुनाव न होने के कारण जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर दबाव है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराई जाए। झारखंड के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नगर निकाय चुनाव का समय और परिणाम राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव भी निकट भविष्य में आने वाले हैं, इसलिए नगर निकायों का जनादेश सरकार और विपक्ष दोनों के लिए संकेतक साबित होगा। हेमंत सोरेन सरकार इन चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी दल भी इसे राज्य में अपनी पकड़ साबित करने का अवसर मान रहे हैं।

कपड़ा उद्योग को केंद्र सरकार की राहत, पीएलआई योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई

(जीएनएस)। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत देते हुए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब अगस्त 2025 में शुरू हुए नवीनतम आमंत्रण राउंड में मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों से भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इस बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने संभावित निवेशकों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि आवेदन विंडो का विस्तार उद्योग जगत की गहरी रुचि और बाजार की संभावनाओं को दर्शाता है। मंत्रालय के

अनुसार, यह कदम न केवल निवेशकों को योजना में भाग लेने का एक और अवसर देगा बल्कि देश के घरेलू वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और मांग को भी सामने लाता है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार निवेश प्रवाह को और मजबूत करेगा तथा भारत को वैश्विक परिधान बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाएगा।

वस्त्र क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना 24 सितंबर 2021 को अधिसूचित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एमएमएफ परिधान और फैब्रिक्स के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उद्योग को बड़ा आकार और पैमाना देना, रोजगार सृजित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और उद्योग को दीर्घकालीन रूप से व्यवहार्य बनाना है।

अब तक 74 कंपनियों को इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया है, जिनका कुल प्रतिबद्ध निवेश लगभग 28,711 करोड़ रुपये है। इन कंपनियों से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन की उम्मीद की जा रही है।

सरकार के इस फैसले को उद्योग जगत ने सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है। विश्लेषकों का मानना है कि तिथि विस्तार से न केवल निवेशकों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकेंगे। इस कदम से भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और "मेक इन इंडिया" पहल को भी बल मिलेगा।

हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है मल्टीमॉडल हब, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य प्रगति पर, स्टेशन बिल्डिंग का लगभग 80% कार्य पूर्ण

रेलवे स्टेशन को शहर से इंटीग्रेट करने के लिए हाइवे तक 12 मीटर चौड़ी नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिससे यात्रियों मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

▸▸ एक एकड़ के करीब विशाल पार्किंग की सुविधा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से प्रगति पर है। स्टेशन भवन का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और आगामी समय में यात्रियों को आधुनिक एवं उत्कृष्ट सुविधाओं से युक्त स्टेशन उपलब्ध होगा। यह पुनर्विकास न केवल यात्री सुविधाओं में वृद्धि करेगा बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

सुविधाएँ:

▸▸ स्टेशन का प्रवेश द्वार 12 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिससे यात्री सहज रूप से स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे।

▸▸ लगभग 4110 यार्ड (करीब एक एकड़ जमीन) की विशाल पार्किंग, जो पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगा।

▸▸ पिक अप/ड्रॉप ऑफ क्षेत्र, जिससे यात्रियों के वाहन ले जाने और छोड़ने में सुविधा होगी।

▸▸ परिसर में आकर्षक लेंडस्केपिंग की गई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए खुला और हरा-भरा वातावरण सुनिश्चित होता है।

▸▸ बड़ा कॉन्कोर्स क्षेत्र, यात्रियों के लिए खुला और व्यवस्थित प्रतीक्षालय की

व्यवस्था है।

▸▸ डीलक्स ए.सी. प्रतीक्षालय एवं नॉन ए.सी. प्रतीक्षालय है, जो सामान्य यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा।

▸▸ फुट ओवर ब्रिज 36 फीट चौड़ा और 67 मीटर लंबा होगा और इसके निर्माण से प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

▸▸ प्लेटफॉर्म-1 कवरशेड 640 वर्गमीटर में फैला है, जबकि प्लेटफॉर्म-2 और 3 कवरशेड 320 वर्गमीटर हैं, जो बारिश और धूप से सुरक्षा प्रदान करेगा।

▸▸ दिव्यांगजन हेतु शौचालय की व्यवस्था।

▸▸ निकास द्वार 12 मीटर चौड़ा है, जिससे स्टेशन से सहज निकास संभव होगा

▸▸ सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग का विकास किया गया है, जिससे वाहन संचालन सुव्यवस्थित होगा।

▸▸ स्टेशन फसाड़ और प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया है।

▸▸ आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण किया गया है, जो बेहतर सुरक्षा, बैठने और टिकटिंग सुविधा प्रदान करेगा।

वर्तमान में हिम्मतनगर स्टेशन पर 12 रेगुलर एवं 4 स्पेशल ट्रेनें रुकती है, यहाँ से प्रतिदिन लगभग 2500 यात्री यात्रा करते है और इस स्टेशन को भविष्य में प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्रियों की आवाजाही और सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

पुनर्विकसित हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सहज यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। यह पुनर्विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी प्रोत्साहन देगा। नया हिम्मतनगर स्टेशन भविष्य में साबरकांठा क्षेत्र के लिए स्मार्ट एवं आधुनिक रेल परिवहन का प्रतीक बनेगा। गुजरात सरकार के सहयोग से स्टेशन से मुख्य मार्ग तक लगभग 100 मीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी स्टेशन एवं स्टेशन पर बन बनाए जा रहे 12 मीटर चौड़े फूटओवर ब्रिज से होगी। यह 12 मीटर चौड़े फूटओवर ब्रिज शहर के दोनों छोरों को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को शहर से एक छोर से दूसरे छोर पर जाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हिम्मतनगर–खेड़ब्रह्मा रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग पर शीघ्र ही रेल सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को तेज़ एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इस नई कनेक्टिविटी से आसपास के शहरों तक रेलवे की पहुँच और मजबूत होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

भावनगर मंडल में 9 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों में एम.एस.टी. (मासिक सीजन टिकट) धारकों को मिली यात्रा की अनुमति

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल में 9 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट (MST) धारकों को यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्णय से दैनिक रेल यात्रियों को किफायती एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एम.एस.टी. की सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो प्रतिदिन कार्यालय, व्यवसाय या अध्ययन हेतु रेलमार्ग से यात्रा करते हैं। इस सुविधा के माध्यम से यात्री रियायती दर पर रेल यात्राएँ कर सकेंगे। यात्रियों को एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों की द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित कोचों में यात्रा की अनुमति दी गई है। सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुपरफास्ट चार्ज देना होगा।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएँ तथा टिकट संबंधी नियमों का पालन करते हुए सुव्यवस्थित यात्रा करें। इस सुविधा के माध्यम से न केवल यात्रियों का समय एवं धन की बचत होगी बल्कि यातायात व्यवस्था और अधिक सरल एवं सुलभ बनेगी।

ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1.ट्रेन संख्या 11463/11464 सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री वेरावल–जूनागढ़–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

2.ट्रेन संख्या 11465/11466 सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री वेरावल–जूनागढ़–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

3.ट्रेन संख्या 12971/12972 बांद्रा–भावनगर सुपरफास्ट – एम.एस.टी. धारक यात्री अहमदाबाद–सुरेन्द्रनगर–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

4.ट्रेन संख्या 19119/19120 अहमदाबाद–सोमनाथ एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री अहमदाबाद–सोमनाथ–अहमदाबाद सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

5.ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–ओखा–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

6.ट्रेन संख्या 19571/19572 राजकोट–पोरबंदर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री राजकोट–पोरबंदर–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

7.ट्रेन संख्या 19205/19206 भावनगर–महुवा एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–महुवा–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

8.ट्रेन संख्या 19207/19208 पोरबंदर–राजकोट एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री पोरबंदर–राजकोट–पोरबंदर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

9.ट्रेन संख्या 20966/20965 भावनगर–साबरमती सुपरफास्ट इंटरसिटी – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–साबरमती–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

चांदलोडिया – खोड़ियार रेलखंड के डबलिंग हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी

(जीएनएस)। रेल मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के चांदलोडिया–खोड़ियार रेलखंड के डबलिंग हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री नवीन गुलाटी के अहमदाबाद मण्डल दौरे के दौरान इस खंड के डबलिंग की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए हरी झंडी दिखाई है।

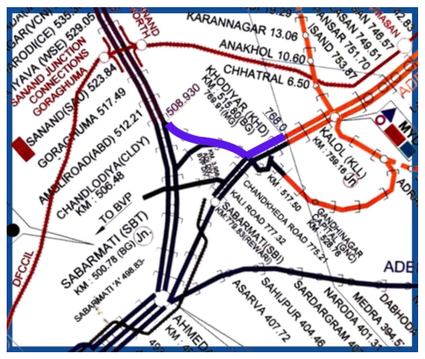

चांदलोडिया 'बी' केबिन से खोड़ियार तक 10 किलोमीटर लंबा यह डबल लाइन प्रोजेक्ट खंड की क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फाइनल लोकेशन सर्वे में एलाइनमेंट, भूमि आवश्यकता, तकनीकी आकलन सहित सभी आवश्यक अध्ययन किए जाएंगे, जिससे भविष्य में संरचना और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की योजना को सटीक और प्रभावी बनाया जा सके। यह कार्य संबंधित इंजीनियरिंग विभाग की टीम द्वारा संपन्न किया जाएगा।

चांदलोडिया – खोड़ियार रेलखंड का परिचालन महत्व

चांदलोडिया – खोड़ियार खंड का परिचालन महत्व अत्यधिक है। यह खंड गांधीनगर कैपिटल को राजकोट और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) क्षेत्र से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। गांधीनगर से चलने वाली सभी ट्रेनें जो राजकोट, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, सोमनाथ और NWR क्षेत्र जैसे जोधपुर, जयपुर, अजमेर आदि की ओर जाती हैं, इसी खंड से होकर गुजरती हैं। भारी यातायात के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की गति और समयबद्ध संचालन में अक्सर चुनौतियाँ आती रही हैं।

डबलिंग के बाद इस खंड की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन में सुधार होगा। यह परियोजना न केवल ट्रेन संचालन की स्थिरता और समयबद्धता को सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में भी योगदान देगी। सौराष्ट्र क्षेत्र को गुजरात की राजधानी गांधीनगर और आगे दिल्ली/उत्तर भारत से जोड़ने वाले मार्ग की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, डबलिंग के माध्यम से मार्ग की भीड़ कम होगी, ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रियों को समय पर सेवाएँ मिलने में सुविधा होगी।

चांदलोडिया – खोड़ियार खंड की डबलिंग से न केवल परिचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास और माल व यात्री परिवहन की सुगमता में भी योगदान देगा। आम जनता और यात्रियों के लिए यह कदम लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

आंबलियासन-विजापुर गेज परिवर्तन कार्य अंतिम चरण में

आम जनता से रेल पटरी से दूर रहने की अपील

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर आंबलियासन से विजापुर के बीच 41.5 किमी लंबी रेल लाइन का गेज परिवर्तन (GC) का कार्य वर्तमान में अंतिम चरण में है। इस संबंध में आम जनता से आग्रह है कि वे रेलवे ट्रैक के पास अनावश्यक रूप से न जाएँ और पूरी सावधानी बरतें। इस समय इस लाइन पर विभागीय ट्रेनें, टेंपिंग मशीनें और अन्य तकनीकी मशीनें ट्रैक पर कार्यरत हैं। आगामी दिनों में इस ट्रैक पर तीव्र गति से ट्रेन का स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। यह ट्रायल रेल परिचालन शुरू करने से पहले की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्थानीय निवासियों, किसानों और राहगीरों से निवेदन है कि वे रेलवे लाइन को अनधिकृत स्थानों से पार न करें। बच्चों और पशुओं को ट्रैक से दूर रखें और किसी भी प्रकार की

असावधानी से बचें। यह रेल लाइन क्षेत्र के लोगों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह कार्य सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

भावनगर-साबरमती सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में 4 अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भावनगर मंडल की भावनगर-साबरमती दैनिक सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में अस्थाई तौर पर अतिरिक्त कोच की सुविधा प्रदान की जा रही है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा हेतु निम्नानुसार अस्थायी व्यवस्था की गई है –

▸▸ ट्रेन संख्या 20966/20965 भावनगर-साबरमती-भावनगर दैनिक सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में 04 (चार) जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

▸▸ यह सुविधा 04 अक्टूबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

रविवार, 05 अक्टूबर, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

▸▸ पश्चिम रेलवे का माहिम एवं सांताक्रुज़ ▸▸ स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार, 04/05 अक्टूबर, 2025 की मध्यरात्रि को माहिम एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर 01.00 बजे से 04.30 बजे तक 3.5 घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक के दौरान डाउन धीमी लाइन की सभी ट्रेनें मुंबई सेंट्रल एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइनों पर चलायी जायेंगी। ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण इन ट्रेनों को लोअर परेल, माहिम एवं खार रोड स्टेशनों पर डबल हॉल्ट दिया जायेगा। इसी प्रकार, अप धीमी लाइन

की ट्रेनें सांताक्रुज़ से मुंबई सेंट्रल/चर्चगेट के बीच अप फास्ट लाइन पर चलायी जायेंगी, जो खार रोड स्टेशन पर डबल हॉल्ट लेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण महिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल एवं महालक्ष्मी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

इस ब्लॉक की विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त ब्लॉक व्यवस्था को ध्यान में रखें।

अतः रविवार, 05 अक्टूबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे
सफाई एवं रंगाई कार्य

मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, डिब्बा मरम्मत कार्यशाला, पश्चिम रेल्वे, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013, ई-निविदा आमंत्रित करते हैं. सूचना संख्या: WR-PL-ME-EST-635019-B, दिनांक: 30.09.2025 कार्य का नाम: बाहरी पीयू पेंटिंग (छत सहित) स्क्रैपिंग सहित,I C F कोचों के अंडरफ्रेम की सफाई एवं रंगाई। विज्ञापित लागत: ₹. 5,56,69,242.30. बयाना राशि: ₹4,28,400/-। ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: दि. 23.10.2025 को दोपहर 14:00 बजे तक. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 0670

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

हरियाणा बनेगा फिर से सियासी सेंटर: दीपावली से पहले पीएम मोदी का संभावित दौरा, भाजपा को मिलेगी नई ऊर्जा

(जीएनएस)। हरियाणा फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बार दीपावली से पहले हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उनका कार्यक्रम अंबाला छावनी में तय हो सकता है, जहाँ वे 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में बन रहे स्मारक का लोकार्पण करेंगे। यदि यह कार्यक्रम अंतिम रूप नहीं ले पाया, तो संभावना है कि प्रधानमंत्री पहली नवंबर को हरियाणा दिवस पर रोहतक पहुंचेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से नाता केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा है। अगस्त 2014 से अब तक उन्होंने 16 बार हरियाणा का दौरा किया है और इस बार यह उनकी 17वीं यात्रा होगी। हर दौरे में उन्होंने राज्य को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी है—चाहे वह किसानों की आय बढ़ाने की पहल हो या गांवों में लंबे समय से बसे परिवारों को मालिकाना हक देने का फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने 17 अक्टूबर को अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार का दावा है कि पिछले एक साल में चार दर्जन से अधिक चुनावी वादे पूरे किए गए हैं और लक्ष्य 90 तक पहुंचने का है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने

'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये सीधे उनके खातों में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री को इस योजना की जानकारी दी और बताया कि पहली नवंबर से महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल, तेलंगाना और पंजाब में भी ऐसी घोषणाएं हुईं, लेकिन वहां अब तक राशि महिलाओं तक नहीं पहुंची, जबकि हरियाणा इस दिशा में देश का पहला राज्य बन रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के लिए भी नैतिक बल साबित होगा। यह लगातार तीसरी बार है जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। नायब सिंह सैनी ने मार्च 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर जिम्मेदारी संभाली थी और अक्टूबर 2024 में जनता के जनादेश से मुख्यमंत्री बने। एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर मोदी का दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन से पहले मुख्यमंत्री सैनी पांच अक्टूबर को जापान रवाना हो रहे हैं। वहां वे एक सप्ताह तक निवेश और तकनीकी सहयोग को लेकर दौरे पर रहेंगे। उम्मीद है कि उनके लौटते ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगेगी। मोदी के हरियाणा दौरे का असर केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रदेश की राजनीति, खासकर आगामी चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। महिलाएं, किसान और युवा—तीन ऐसे वर्ग हैं जिन पर भाजपा हमेशा फोकस करती रही है। इस दौरे के दौरान भाजपा इन वर्गों को केंद्र में रखकर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर काम करेगी। इस तरह हरियाणा फिर से चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है, और प्रधानमंत्री का दौरा इसे और अधिक सियासी महत्त्व देगा।

अमेठी में 20 वर्षीय युवक का शव फंदे से मिला, पुलिस ने शुरू की जांच

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शुक्रवार को एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान देवगन चौहान (20 वर्ष) के रूप में हुई है, जो शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के सेवरा गांव का रहने वाला था। शव शुक्रवार सुबह घर के अंदर फंदे से लटका मिला। शुकुल बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक अभिनेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि मृतक के मानसिक स्थिति और किसी भी तरह के विवाद या दबाव के कारणों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा। इस घटना ने गांव में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के पीछे के असली कारणों की पुष्टि होगी।

राजस्थान में मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई: 1,000 किलोग्राम गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

(जीएनएस)। राजस्थान पुलिस ने झुंझुनू जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल और झुंझुनू जिला विशेष टीम ने मिलकर पांच करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया और दो प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई प्रहार नामक अभियान के तहत की गई, जिसे पुलिस को एक विशिष्ट खुफिया सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया।

सूचना के अनुसार, गांजे की यह खेप ओडिशा से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आ रही थी। तस्करों ने इसे एक कंटेनर ट्रक में छिपा रखा था, जिसमें गांजे को चालक की सीट के पीछे विशेष रूप से निर्मित चैंबर में रखा गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) दिनेश एमएन ने बताया कि सूचना के आधार पर झुंझुनू जिले के

उदयपुरवाटी इलाके में नाकाबंदी की गई और वाहन को रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस को कुल 1,014 किलोग्राम गांजे की बोरियां बरामद हुईं। अधिकारियों के अनुसार, यह खेप शेखावाटी में मादक पदार्थों के माफिया राजू पचलेंगी और गोकुल के लिए भेजी जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान तस्करी नेटवर्क के दो प्रमुख सदस्य सुभाष गुर्जर और प्रमोद गुर्जर को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सीकर निवासी के रूप में हुई।

एडीजी ने बताया कि यह सिर्फ एक जब्ती नहीं है, बल्कि मादक पदार्थों के संगठित आपूर्ति नेटवर्क पर की गई एक "सर्जिकल स्ट्राइक" है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से तस्करी के बड़े नेटवर्क को भारी झटका लगेगा और अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान जैसे राज्य, जो भौगोलिक रूप से तस्करी मार्गों के बीच में स्थित हैं, वहां मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। इस तरह की सफल कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को मज़बूत करती है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में भी सहायक होती है।

पुलिस अब इस गिरफ्तारी से जुड़े और अन्य नेटवर्क के सदस्यों की पहचान और उनके पीछे के संगठन को तोड़ने के लिए गहन जांच कर रही है। इसके अलावा बरामद गांजे की परीक्षण और निपटान प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि राज्य में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

केरल के कन्नूर में भाजपा नेता के घर पर बम हमला, पुलिस जांच में जुटी

(जीएनएस)। केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय भाजपा नेता विजू नारायणन के घर पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे बम फेंकने की घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। घटना कन्नपुरम क्षेत्र में हुई, जहाँ भाजपा नेता के माता-पिता घर पर मौजूद थे। हालांकि, इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर की खिड़कियों और कुछ दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा है।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और घटना की जांच शुरू कर दी। सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते को स्थानीय आवासीय परिसर और आसपास के इलाके में तैनात किया।

घटना के बाद भाजपा ने हमले

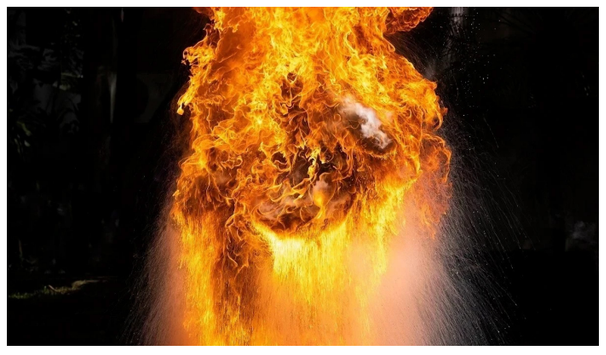

के पीछे माकपा का हाथ होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस इस मामले में मिलीभगत कर रही है और उनकी शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, वाम दल ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और कहा कि उनकी पार्टी का इस हमले से कोई संबंध नहीं है।

विशेषज्ञों और स्थानीय नेताओं का मानना है कि यह हमला राजनीतिक तनाव और चुनावी माहौल को और बढ़ा सकता है। घटना ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं।

पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और बम हमले के पीछे के संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। यह घटना केरल में राजनीतिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं को भी उजागर करती है, जहाँ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले समय-समय पर होते रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं कि वह जल्द ही हमले के पीछे के दोषियों की पहचान कर सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाए।

तेज प्रताप का तेजस्वी पर निशाना: कहा, "राम और लक्ष्मण जैसी मर्यादा का पालन करें छोटे भाई"

(जीएनएस)। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) परिवार की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर विवादास्पद बयान दिया। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी को अपने बड़े भाई के प्रति वही सम्मान दिखाना चाहिए, जैसा भगवान राम को उनके अनुज लक्ष्मण से मिला था।

हसनपुर से राजद के निष्कासित विधायक तेज प्रताप से जब सवाल किया गया कि पार्टी में रहते हुए वे अपने समर्थकों को बागी उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा देते थे, तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ''छोटे भाई होने के नाते उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए, जैसे लक्ष्मण ने राम के मामले में किया था। वह ऐसे लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, जो जयचंद जैसे हैं।''

तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा उन लोगों की ओर था, जो राजद के भीतर राजनीतिक लाभ के लिए तेजस्वी को प्रभावित कर रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लंबे समय से टकराव चला आ रहा है। राजद में तेजस्वी के करीबी सहयोगियों, जिनमें राज्यसभा सदस्य संजय यादव भी शामिल हैं, के साथ तेज प्रताप अक्सर मतभेद रखते रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने आलोचकों की तुलना जयचंद से की, जो इतिहास में प्रतिद्वंद्वी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी की मदद करने वाला शासक माना जाता है।

राजनीतिक योजना पर स्पष्ट करते हुए तेज प्रताप ने घोषणा की कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह वही सीट है, जो तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से सटी हुई है और जहां से तेज प्रताप ने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपना राजनीतिक पदार्पण किया था। इस कदम से माना जा रहा है कि तेज प्रताप सीधे अपने छोटे भाई के क्षेत्रीय प्रभाव के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तेज प्रताप ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ''आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं।'' वहीं, ''आई लव मोहम्मद'' विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास कुरान शरीफ की प्रति है और वे पैगंबर का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विवाद को केवल माहौल खराब करने के लिए खड़ा किया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, तेज प्रताप का यह बयान केवल परिवारिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजद के भीतर और बिहार की राजनीति में बड़े संघर्ष का संकेत देता है। तेज प्रताप का महुआ से चुनाव लड़ने का निर्णय तेजस्वी के क्षेत्रीय प्रभुत्व को चुनौती देने के इरादे के रूप में देखा जा रहा है।

इस बयान के बाद राजद परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और आने वाले दिनों में दोनों भाईयों के बीच राजनीतिक टकराव और तीव्र हो सकता है।

मप्र के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ और शावकों की मौत, वन विभाग ने किया जांच शुरू

(जीएनएस)। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बृहस्पतिवार को वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन गया। दो अलग-अलग स्थानों पर रिजर्व के मुखी रेंज और कान्हा रेंज में एक वयस्क बाघ और दो शावक मृत पाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृत बाघ और शावकों की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुखी रेंज में एक वयस्क बाघ मृत पाया गया। वन अधिकारियों का मानना है कि यह बाघ आपसी संघर्ष या क्षेत्रीय दखल के कारण मारा गया हो सकता है। कान्हा रेंज में पाए गए लगभग दो महीने के दो मादा शावकों की मृत्यु का कारण प्राथमिक जांच के अनुसार बाघ के हमले को माना जा रहा है। पोस्टमार्टम से इसकी पुष्टि की संभावना है। शावकों की मौत ने वन्यजीव विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह संकेत करता है कि युवा बाघों और शावकों के संरक्षण में चुनौतियाँ मौजूद हैं।

वन विभाग ने बताया कि मृत बाघ का

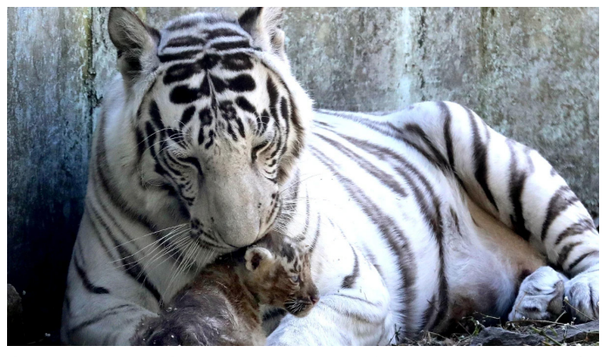

पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारियों ने क्षेत्र में पैट्रोल बढ़ा दिया है और आसपास के क्षेत्र में अन्य बाघों और शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय शुरू कर दिए हैं।

कान्हा टाइगर रिजर्व, जो देश के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है, में इस तरह की घटनाएँ वन्यजीव संरक्षण की जटिलताओं को उजागर करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बाघों के आपसी संघर्ष और शावकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि युवा प्रजातियों की संख्या और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखा जा सके।

वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों ने कहा कि यह घटना चेतावनी का संकेत है कि रिजर्व में बाघों की संख्या और उनके व्यवहार पर लगातार नजर रखना आवश्यक है। कान्हा रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या और उनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पिकनिक बना मातम, अरब सागर में डूबे एक ही परिवार के तीन सदस्य, चार अब भी लापता

(जीएनएस)। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के आठ लोग अचानक समुद्र की लहरों की चपेट में आ गए। शाम लगभग चार बजे हुई इस घटना में तीन सदस्यों की मौत हो चुकी है और चार अन्य अब तक लापता हैं। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय आपदा प्रबंधन दल ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन समुद्र की गहराई और तेज धाराओं के कारण तलाशी अभियान बेहद कठिन हो गया।

जानकारी के अनुसार यह परिवार बेलगाम (कर्नाटक के बेलगावी) से घूमने आया था, जबकि परिवार के दो सदस्य सिंधुदुर्ग के कुडाल में ही ठहरे हुए थे। कुल आठ लोग समुद्र तट पर पहुंचे और मस्ती के मूड में एक साथ पानी में उतर गए। शुरुआती तौर पर उन्हें समुद्र की गहराई और लहरों की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। धीरे-धीरे लहरें और धाराएँ उन्हें गहरे पानी की

ओर खींच ले गईं। देखते ही देखते परिवार के लोग डूबने लगे और बीच पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस, गोताखोरों और आपदा प्रबंधन दल ने मौके पर पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद तीन लोगों के शव समुद्र से बाहर निकाले जा सके, लेकिन चार अन्य अभी तक लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि देर शाम तक तलाशी अभियान जारी रहा और संभावना है कि अगले दिन भी खोज अभियान जारी रहेगा। यह हादसा समुद्र तट पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेतों की कमी को भी उजागर करता है। स्थानीय प्रशासन ने पहले भी पर्यटकों को सावधान रहने की सलाह दी थी, क्योंकि इस तट पर धाराएँ तेज़ और गहराई अचानक बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग लापरवाही कर बैठते हैं, जिसका नतीजा जानलेवा साबित होता है। घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। बेलगाम से आए इस परिवार की खुशियाँ कुछ ही घंटों में गम में बदल गईं। परिवार के बाकी सदस्य और स्थानीय लोग लगातार समुद्र किनारे लापता लोगों की खोज में जुटे हैं, उनकी आँखें इस उम्मीद पर टिकी हैं कि शायद बचाव दल उनके प्रियजनों को ढूँढ निकालें।

सिंधुदुर्ग पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश पूरी गंभीरता से की जा रही है और गोताखोर रात तक अभियान में लगे रहे। लेकिन समुद्र की लहरें और अंधेरा इस मिशन को और कठिन बना रहे हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि समुद्र में तैरने के दौरान सावधानी बरतें और निर्धारित सीमा से बाहर न जाएँ।

अरब सागर की लहरों ने इस परिवार की खुशियों को पलभर में छीन लिया। जो लोग पिकनिक मनाने निकले थे, उनके घर अब मातम में डूब गए हैं। यह हादसा एक करुण संदेश छोड़ गया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी घातक साबित हो सकता है।

सीबीआई का बड़ा ऑपरेशन, 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया रक्षा लेखा महानियंत्रक का अधिकारी

(जीएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि उसने वायुसेना केंद्र पर सीसीटीवी लगाने के लिए आपूर्ति आदेश को मंजूरी देने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

यह मामला गांधीनगर, गुजरात से जुड़ा है, जहाँ एक सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने सीबीआई को शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) कार्यालय के लेखा परीक्षक/कार्मिक अशोक कुमार जाधव और वायुसेना के एक हवलदार ने मिलकर 2.5 करोड़ के अनुबंध आदेश को पास करने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत माँगी। यह रकम लगभग 2% कमीशन के बराबर थी।

सीबीआई ने शिकायत मिलने के

बाद पूरी सावधानी से जाँच शुरू की। सत्यापन के दौरान यह साफ हो गया कि रिश्वत की मांग असली थी। हालांकि, वायुसेना का हवलदार फोन पर बात करने से बचता रहा, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिकॉर्डिंग से उसकी भूमिका भी सामने आ गई।

सीबीआई की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। सोमवार को जाल बिछाया गया और जाधव को 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई के प्रवक्ता ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को अहमदाबाद के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुणे लाया गया। इसके बाद पुणे के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश करने पर उसे 4 अक्टूबर, 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि रक्षा सौदों जैसे संवेदनशील मामलों में भ्रष्टाचार किस तरह पैर पसारने की कोशिश करता है। अनुबंधों और आपूर्ति आदेशों में रिश्वतखोरी राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिए खतरनाक है।

इस घटना के बाद रक्षा क्षेत्र में काम कर रही अन्य कंपनियाँ और अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में आगे और पूछताछ कर सकती है और यह भी संभव है कि रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हों।

पकड़े गए अधिकारी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि करोड़ों के सरकारी अनुबंधों को मंजूरी देने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को और कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि ईमानदार कंपनियों को किसी दबाव या रिश्वत की मांग का सामना न करना पड़े।